

2036/2010

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2014

Order

Dated Shimla-171002, the 14-10-14

- Sub :-** जिला शिमला में रोहरू वन प्रभाग के अन्तर्गत नाडू-निगली (कि०मी० ०/०० से ०/३५०) के निर्माण हेतु ०.७२ हे० वन भूमि का हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तन । भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय मध्य क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम १९८० के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या ९-HPB511/2010-CHA/349 दिनांक १९.०९.१४ के परिणामस्वरूप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित ०.७२ hectares वन भूमि को Ex-Engineer, B & R Division, Rohru, Distt. Shimla, H.P. को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करती है।
- वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
 - प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के दुगुने वन भूमि अर्थात् १.४४ हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।
 - सक्षम स्तर से शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि में यदि कोई बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०बी० की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।
 - प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा डम्पिंग साइट का रिक्लेमेशन योजना कार्यान्वित किया जाएगा। वन मण्डल अधिकारी निजी तौर पर इस शर्त के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा कि मलबा स्थल का उचित रूप से Reclamation कर दिया गया है।
 - मलबे का प्रयोग स्थानिय रूप से पुख्ता-दीवार (Retaining Wall) के पीछे गड़दों को भरने/ढलानों के सुधार के लिए किया जायेगा। इसे पहाड़ी ढलान के नीचे बिल्कुल नहीं गिराया जायेगा तथा न ही नालों आदि में गिराया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
 - यदि कोई अन्य संबंधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
 - परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।
 - प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
 - प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टॉफ को रसोई गैस / किरासिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।
 - प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
 - प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से / पर निर्माण कार्य के दौरान मिटटी / पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।
 - प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतापजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

आदेश अनुसार
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -२

Endst. No FFE-B-F(2)-3/2014 (FCA)

Dated, Shimla-171001 the,...

For
Final Approval

P.T.O